हरियाणा किसान आयोग
समाचार पत्रिका

खण्ड 1, अंक 3 | त्रैमासिक समाचार पत्रिका | जुलाई-सितम्बर, 2011

इस अंक में

- टिकाऊ कृषि पर चर्चा
- उत्कृष्टता के लिए हरियाणा कृषक पुरस्कार
- हरियाणा में पशुपालन पर कार्यदल की बैठक
- हरियाणा में मात्स्यिकी विकास पर कार्यशाला
- हरियाणा में संरक्षित कृषि पर कार्यशाला
- आयोग की पांचवीं बैठक
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यदल की बैठकें व भ्रमण
- हरियाणा में बागवानी विकास कार्यदल का गठन
- हरियाणा में संरक्षित कृषि कार्यदल का गठन
- पशुपालन पर विशेषज्ञों की बैठक
- मत्स्य कृषकों के साथ परिचर्चा बैठक
- एल. एल. आर. यू. वी. ए. एस. के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप
- हरियाणा को ''कृषि कर्मण'' पुरस्कार
- श्री अशोक यादव का ब्रिस्बेन, आस्ट्रेलिया में पत्र प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष की कलम से

हरियाणा किसान आयोग अब अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। इसमें से कुछ आरंभिक समय क्रियाशील कार्यालयों को स्थापित करने, उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने और जन शक्ति को व्यवस्थित करने में लगा। इसके पश्चात कुछ समय पूरे राज्य के किसानों के साथ परिचर्चा बैठकें आयोजित करने, विशेषज्ञ कार्यदलों के गठन तथा समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु भागीदारी के माध्यम से योजना बनाने में लगा। इस समय हम ऐसी उचित अनुशंसाओं के साथ प्राप्त होने वाले विकल्पों व विभिन्न सुझावों के विश्लेषण में लगे हैं जिनसे हरियाणा के किसानों की तत्कालीन समस्याओं को हल करने में सहायता मिल सकती है।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आयोग ने किसानों के साथ हुई परिचर्चा के आधार पर ''नीतिगत मुद्दों और विकल्पों पर रिपोर्ट'' शीर्षक से अपनी प्रथम रिपोर्ट को अंतिम रुप दे दिया है। यह रिपोर्ट अक्तूबर 2011 में माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट में उन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें परिचर्चा बैठकों के दौरान किसानों ने उठाया था और इसमें राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ प्राथमिकतापूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। आयोग इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करता रहेगा। ''हरियाणा की कृषि नीति'' के लिए गठित कार्यदल ने भी रिपोर्ट का प्रथम मसौदा तैयार कर लिया है। इसे और अधिक सुधारने तथा वांछित सुझावों के लिए सम्बंधित व्यक्तियों के बीच परिचालन कर जांचा-परखा जा रहा है। ऐसी आशा है कि आयोग इस वर्ष के अंत तक सरकार को ''हरियाणा की कृषि नीति'' पर तैयार किया गया मसौदा प्रस्तुत कर देगा। इसके अतिरिक्त छह और दल भी गठित किए गए हैं। ये भी वैज्ञानिकों, फील्ड कर्मियों, विस्तार अधिकारियों तथा किसानों के साथ अनेक बैठकें/परामर्श कर रहे हैं। ''संरक्षण कृषि'' पर व्यापक रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। हम विभिन्न दलों से रिपोर्टों की अपेक्षा कर रहे हैं और हमारी यह आशा है कि उनकी सिफारिशों से हरियाणा में कृषि के सकल विकास व इसकी वृद्धि में सहायता मिलेगी।

संतोष का विषय है कि आयोग को राज्य सरकार, वैज्ञानिक समुदाय तथा प्रगतिशील किसानों से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। अत: मैं इस अवसर पर इन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह आशा भी करता हूं कि हमें भविष्य में भी ऐसी ही सहायता व सहयोग मिलते रहेंगे।

(आर.एस. परोदा)

टिकाऊ कृषि पर चर्चा

उष्ण कटिबंधीय विकासशील देशों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भूख से जुड़ी समस्याएं जैसे प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मामले में और अधिक गंभीर होने की संभावना है। साथ ही श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली भूमि तथा जल की उपलब्धता में निरंतर कमी आ रही है जबकि ये दोनों पर्याप्त मात्रा में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का उत्पादन करने की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं। यह खाद्यान्न देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए नितांत आवश्यक है। परिस्थिति की मांग है कि मानव जाति तथा अन्य जीवों की जनसंख्या का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम भूमि और जल से और अधिक गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उत्पन्न किया जाए और इसके लिए मिट्टी तथा अन्य संसाधनों का स्वास्थ्य बेहतर रखने की आवश्यकता है।

हरियाणा ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में बहुत प्रगति की है जिससे यह राष्ट्रीय खाद्य भंडार का आधार बना हुआ है। हरित क्रांति ने राज्य के कुल 86 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र अर्थात् 4.42 मिलियन हैक्टर को खेती के अंतर्गत लाने में सहायता की और यहां की फसल गहनता 180 प्रतिशत रही। तथापि, घटती हुई घटक उत्पादकता, असंतुलित पोषण और गिरता हुआ मृदा स्वास्थ्य, वर्तमान उत्पादन क्रियाविधियों की अक्षमता, संसाधनों, विशेषकर श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बीज और जल की कमी, उर्वर कृषि भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों में उपयोग, समेकित फार्मिंग प्रणालियों के लिये विशिष्ट मॉडल के न होने तथा उचित नीतियों की कमी के कारण हाल ही में कृषि उत्पादन दर में या तो ठहराव की प्रवृत्ति देखी गई है या इसमें गिरावट आई है। निश्चय ही इससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति जटिल हो गई है और इसमें जलवायु परिवर्तन का भी योगदान है। अत: यदि किसानों को मृदा और फसल प्रबंधन की ऐसी उचित विधियां अपनाने के लिए तैयार नहीं किया गया जिनसे संसाधन संबंधी बाधाएं कम हों और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव में कमी लाई जा सके तो स्थिति के और जटिल होने की संभावना है।

हरित क्रांति से आगे बढ़कर सदाबहार क्रांति लाने के लिए हमें विशिष्ट फसलीय दृष्टिकोण से हटकर समेकित फार्मिंग प्रणाली दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा। जल तथा अन्य संसाधनों की उत्पादक एवं आर्थिक दक्षता, उचित फसलों/किस्मों का चयन, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई तथा ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी, कम लागत वाली संरक्षण कृषि विधियों को अपनाने, ग्रामीण परिवारों के लिए सस्ते व उर्जा के नए-नए व बार-बार इस्तेमाल होने वाले साधनों के सृजन और मूल्यवर्धन के साथ-साथ स्थान विशिष्ट फार्मिंग प्रणाली मॉडल तैयार करने, संसाधनहीन व कम संसाधन वाले छोटे किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए उनके कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण व विपणन की जरुरत है इसके साथ भारत एवं हरियाणा राज्य में सिंचित व बारानी पारिस्थितिक प्रणालियों में भी किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रसंस्करण व विपणन की सुविधा दिलाने जैसे मुद्दों की अत्याधिक आवश्यकता है।

उपरोक्त विषय पर एक व्याख्यान हरियाणा किसान आयोग की ओर से डॉ डी. पी. सिंह ने 9 जुलाई 2011 को जींद, हरियाणा में ''हरियाणा कृषि प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान'' में दिया था।

उत्कृष्टता के लिए हरियाणा कृषक पुरस्कार

हरियाणा के दो प्रगतिशील किसानों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। श्री ईश्वर सिंह कुण्डू, निवासी-ग्राम व डाकखाना केलरम, जिला कैथल ने प्रतिष्ठित ''जगजीवन राम नव खोज कृषक पुरस्कार'' प्राप्त किया जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के किसानों के लिए था। श्री कुण्डू को यह पुरस्कार 16 जुलाई 2011 को नई दिल्ली में भारत सरकार के माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री हरीश रावत ने प्रदान किया।

श्री ईश्वर सिंह कुण्डू पुरस्कार प्राप्त करते हुए

श्री कंवल सिंह चौहान, निवासी - ग्राम व डाकखाना अटेरना, जिला सोनीपत को हरियाणा के प्रगतिशील किसान के रुप में ''विविधीकृत कृषि के लिए एन. जी. रंगा कृषक पुरस्कार 2010'' प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने फार्म पर ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, केंचुआ की खाद बनाने तथा फलों व सब्जियों की तुड़ाई/कटाई उपरांत मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।

श्री कंवल सिंह चौहान पुरस्कार प्राप्त करते हुए

हरियाणा में पशुपालन कार्यदल की बैठक

पशुपालन पर कार्यदल ने लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों व वैज्ञानिकों तथा प्रगतिशील पशुपालकों व उद्यमियों के साथ 22 और 23 जुलाई 2011 को हिसार में परिचर्चा बैठकें आयोजित कीं। इस दल ने हरियाणा में पशु अनुसंधान फार्म, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग, पशु जैवप्रौद्योगिकी और पशुचिकित्सालय परिसर का भ्रमण भी किया तथा वहां चल रहे विभिन्न अनुसंधान कार्यों व विकासात्मक क्रियाकलापों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा राज्य के पशुधन को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में आरंभिक जानकारी प्राप्त की। किसानों तथा उद्यमियों ने कार्यदल को उनके समक्ष आने वाली बाधाओं और रुकावटों से अवगत कराया तथा इन समस्याओं को हरियाणा किसान आयोग द्वारा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। कुछ प्रमुख मुद्दे थे : प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर बिक्री दर में कमी करना, डेयरी के लिए दिए जाने वाले कर्ज को रियायती दर पर उपलब्ध कराना तथा बिजली प्रभार को कृषि के क्षेत्र में लिए जाने वाले प्रभार के समकक्ष लाना। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि राज्य में पशुपालन को विकसित करने के लिए ये मुद्दे राज्य सरकार के समक्ष लाए जाने चाहिए। व्यवसायविदों, किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की क्षमता निर्माण; पशु चारे और आहार के वैकल्पिक स्रोतों; कृषि-वानिकी; डेयरी अर्थशास्त्र; स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन; चारा उत्पादन को बढ़ाने तथा डेरी फार्मिंग आदि जैसे मुद्दों में विश्वविद्यालय की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

पशुधन विकास बैठक के प्रतिभागी

हरियाणा में मात्स्यिकी विकास पर कार्यशाला

हरियाणा किसान आयोग द्वारा 30 जुलाई 2011 को हिसार में ''हरियाणा में मात्स्यिकी विकास : चुनौतियां एवं अवसर'' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मात्स्यिकी कार्य दल के सदस्यों; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार; केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान; महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय; गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना के अधिकारियों व वैज्ञानिकों; निदेशक सहित राज्य के मात्स्यिकी विभाग के प्रतिनिधियों; नाबार्ड; राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड; तथा मत्स्य पालक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. आर.एस.परोदा ने की। कार्यशाला में लवण प्रभावित क्षेत्रों में जलजंतुपालन विकास, प्रौद्योगिकी तथा नीति संबंधी विकल्प, अनुसंधान के लिए क्षमता निर्माण, शिक्षा, विस्तार प्रणालियों एवं विपणन, संस्थागत तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ताकि हरियाणा में मात्स्यिकी को बढ़ावा दिया जा सके तथा किसानों की आय में वृद्धि हो सके। डॉ. आर.एस.परोदा ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में हरियाणा के किसानों की पोषणिक सुरक्षा तथा आय को बढ़ाने के लिए जल तथा जैविक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए विविधीकृत व समेकित कृषि की महत्ता और इसके क्षेत्र व इसकी क्षमता पर बल दिया। केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के निदेशक व मात्स्यिकी पर कार्यदल के अध्यक्ष डॉ. डब्ल्यू.एस. लाकड़ा ने राज्य में विभिन्न प्रकार के जल संसाधनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे व संस्थागत सुविधाओं, इस क्षेत्र की शक्तियों, कमियों व अनुसंधान के विषयों पर प्रकाश डाला। डॉ. वास ने वैज्ञानिक आधार पर मात्स्यिकी के सकल विकास की इच्छा व्यक्त की जिसमें उन्होंने खेल तथा अलंकारिक मात्स्यिकी को भी शामिल किए जाने पर बल दिया। डॉ.विष्णु भट्ट, मात्स्यिकी विकास आयुक्त, भारत सरकार ने विशेषकर मछली बीज उत्पादन, तालाबों के नवीकरण तथा विकास, आहार तथा अन्य निवेशों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। इस बात पर बल दिया गया कि राज्य के नव स्थापित पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी विभाग भी होना चाहिए। कम लवणीय जल में झींगा पालन तथा उच्च लवणीय जल में झींगा पालन, सी-बास के बीज उत्पादन व पालन के लिए उच्च मूल्य वाले मत्स्य पालन हेतु रिसर्कुलेटरी प्रणाली को अपनाने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। मुलेट तथा टाइगर झींगा , नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत तिलापिया के पालन तथा संकुल कार्प पालन पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया। मछलियों के बारे में जन-सामान्य में जागरुकता उत्पन्न करने तथा उनके विविध उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए गुड़गांव तथा राज्य के 4-5 अन्य स्थानों पर एक्वेरियमों के विकास और जल के किफायती उपयोग व सामुदायिक स्वामित्व के लिए उचित नीतियां तैयार करने पर विशेष बल दिया गया।

मात्स्यिकी विकास पर बैठक के प्रतिभागी

हरियाणा में संरक्षित कृषि पर कार्यशाला

हरियाणा किसान आयोग ने 6 अगस्त 2011 को हिसार में ''हरियाणा में संरक्षित कृषि'' के लिए कार्य योजना की समीक्षा करने व इसके विकास हेतु एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग; श्री रोशन लाल, प्रधान कृषि सचिव व वित्त आयुक्त और सदस्य, हरियाणा किसान आयोग; डॉ. के.एस. खोकर, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; डॉ. आर.एस. दलाल, सदस्य-सचिव, हरियाणा किसान आयोग; डॉ राज गुप्ता, प्रमुख, सिमिट, भारत व वहां के वैज्ञानिकों के एक दल; डॉ. वी.एस. आर्य, हरसेक; श्री अशोक यादव, महानिदेशक, कृषि, हरियाणा सरकार; चौधरी चरण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अनेक वैज्ञानिकों, हरियाणा किसान आयोग के परामर्शकों व अन्य स्टाफ और संरक्षण कृषि से जुड़े प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में चार सत्र आयोजित किए गए जिनमें संरक्षित कृषि की प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर आधारित अनुसंधान आवश्यकताओं, अल्प तथा दीर्घावधि कार्य योजनाओं व नीतियों तथा संरक्षित कृषि के लिए वित्तीय सहायता जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला का समापन हरियाणा राज्य में टिकाऊ फसलोत्पादन के लिए संरक्षित कृषि संबंधी कार्यों पर महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के साथ-साथ कार्यदल व भावी कार्य योजना के संबंध में उचित अनुशंसाओं के साथ हुआ।

संरक्षित कृषि पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेते हुए प्रतिनिधि

आयोग की पांचवी बैठक

हरियाणा किसान आयोग की पांचवी बैठक डॉ आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2011 को हिसार में आयोजित की गई। आयोग ने राज्य के लिए कृषि नीति पर कार्यदल द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की तथा इस मसोदें पर और अधिक व्यापक परामर्श व चर्चा करने का निर्णय लिया। आयोग ने संरक्षित कृषि रिपोर्ट पर भी चर्चा की और यह निर्णय लिया कि इस उद्देश्य से आयोजित की गई कार्यशाला में हुई चर्चाओं के प्रकाश में इसे संशोधितों के सुझावों के लिये भेजा जाना चाहिए। आयोग ने कार्य दलों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा उनकी कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यदल की बैठकें व भ्रमण

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कार्यदल के अध्यक्ष डॉ आई.पी. एब्रॉल, पूर्व उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), भा.कृ.अ.प. हैं तथा डॉ. एस.आर.सिंह, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार; डॉ. एच.एस.लोहान, पूर्व अतिरिक्त कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार; डॉ. डी.पी.सिंह, परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग के सदस्य व नोडल अधिकारी हैं। इस दल ने अनेक बैठकें आयोजित कीं तथा विभिन्न संगठनों जैसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विभिन्न क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बावल, करनाल, कौल, सिरसा) व भा.कृ.अ.प. के संस्थानों केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल; कपास अनुसंधान क्षेत्रीय केन्द्र - भा.कृ.अ.प. , सिरसा के साथ-साथ सिंचाई जल वितरण तथा भंडारण संरचनाओं (साहिबी नदी पर मसानी बांध, जिला रेवाड़ी, हांसी- बुटाना नहर और टोहाना नहर शीर्ष प्रणाली, जिला कैथल तथा झज्जर नदी पर ओटू झील, जिला सिरसा) का 8-12 अगस्त 2011 के बीच दौरा किया। कार्यदल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारों क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों और भा.कृ.अ.प. के उपरोक्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों में जो विशिष्ट मुद्दे उभर कर सामने आए उनमें राज्य में मृदा तथा जल संसाधन, जैव विविधता, वनस्पतिक आच्छादन, जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती तथा उत्पादन प्रणाली का गहनीकरण करने जैसे मुद्दे शामिल थे। कार्यदल के सदस्यों ने झज्जर और रोहतक जिलों के दो गांवों में जलाक्रांत क्षेत्रों का भी दौरा किया। दल ने कृषि एवं जल संरक्षण तथा सिंचाई विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जिसमें कुछ चुने हुए किसान भी शामिल हुए। इस चर्चा में जो मुद्दे लिए गए उनमें जलाक्रांत लवणीय क्षेत्र की उप सतही जल निकासी और उसका सुधार का मुद्दा प्रमुख था। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों व अधिकारियों, सिंचाई अभियंताओं, फील्ड कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ हुई यह चर्चा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से जुड़ी स्थान विशिष्ट समस्याओं को समझने में बहुत फलदायक रही। इस जानकारी का उपयोग प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा लिखी जाने वाली अपनी अंतिम रिपोर्ट में किया जाएगा।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कार्यदल के सदस्य वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करते हुए

हरियाणा में बागवानी विकास कार्यदल का गठन

हरियाणा किसान आयोग ने बागवानी पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा करने व बागवानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पहचानने तथा उनकी जांच करने व बागवानी के क्षेत्र में सशक्त निवेश के द्वारा अनुसंधान विकास करने के लिए बागवानी पर एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल के अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उप महानिदेशक (बागवानी) तथा राष्ट्रीय प्राध्यापक (बागवानी) डॉ. के.एल. चड्ढा हैं। इस कार्यदल में विभिन्न पृष्ठभूमि के सदस्य हैं जिनमें शामिल हैं: डॉ. पी.सी. गुप्ता, पूर्व निदेशक, बागवानी तथा कार्यपालक निदेशक, बागवानी, हरियाणा विकास बोर्ड; डॉ. ओ.पी. पारीक, पूर्व निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान; और डॉ. प्रेमानंद दास, अध्यक्ष, द साइंस फाउंडेशन फार ट्राइबल एंड रुरल रिसोर्स डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। यह कार्यदल राज्य में बागवानी के प्रवर्धन के माध्यम से कृषि विविधीकरण की क्षमता की पहचान करेगा; बुनियादी ढांचे सहित राज्य में बागवानी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, भावी प्रशिक्षण तथा जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध मानव संसाधन की पर्याप्तता व अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा के अलावा गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता, शहरी तथा परिनगरीय बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अवसरों, वर्तमान प्रवृत्तियों, सब्जी वाली फसलों और फूलों की संरक्षित खेती की क्षमता व कार्यनीतियों, प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर आधारित ग्रामीण अवसरों, बागवानी व्यापार में सार्वजनिक-निजी साझीदारी की वर्तमान स्थिति की जांच-परख करेगा; और सहयोग के भावी क्षेत्रों की पहचान करेगा।

हरियाणा में संरक्षित कृषि कार्यदल का गठन

संरक्षित कृषि तथा नर्सरी उत्पादन प्रौद्योगिकी एक लाभदायक एवं व्यवहारिक व्यवसाय है और इसे वाणिज्यिक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है जिससे बेमौसमी तथा गुणवत्तापूर्ण सब्जियों और पुष्पों को उगाने में सहायता मिलेगी। हरियाणा किसान आयोग ने संरक्षित कृषि पर एक कार्यदल का गठन किया है जिसके अध्यक्ष डॉ. ब्रह्म सिंह, पूर्व निदेशक, जीवविज्ञान, डी.आर.डी.ओ. हैं तथा डॉ. बलराज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक व प्रभारी, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केन्द्र, भा.कृ.अ.सं.; डॉ. रमेश कुमार, परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान, भा.कृ.अ.सं.; और डॉ. एस.के.अरोड़ा, पूर्व प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार इस कार्यदल के सदस्य हैं। यह कार्य दल राज्य में संरक्षित कृषि व वर्तमान संरचनाओं तथा डिजाइनों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए उपयुक्त कम लागत वाले मॉडल सुझाएगा; संरक्षित कृषि के अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा; सब्जियों/पुष्पों के पूरे वर्ष उत्पादन के लिए विशिष्ट फसलों और उनके क्रमों के बारे में सुझाव देगा व उनकी नर्सरियां उगाने के बारे में अनुशंसाएं करेगा। इसके साथ ही यह दल किसानों की आय बढ़ाने के लिए परिनगरीय कृषि में संरक्षित खेती के उपयोग पर सुझाव देगा, बाजार के साथ प्रभावी सम्पर्कों को बढ़ावा देने के लिए वांछित उपायों की पहचान करेगा, संरक्षित कृषि के संबंध में वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों व सुविधाओं के साथ-साथ मानव संसाधन विकास संबंधी उपायों का मूल्यांकन करेगा; संरक्षित कृषि को सबल बनाने में सार्वजनिक-निजी भूमिका का आकलन करेगा और निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के लिए उचित नीतिगत उपाय सुझाएगा, संरक्षित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की वर्तमान नीतियों व कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और संरक्षित कृषि का उपयोग करके सब्जी वाली फसलों व पुष्पों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीतियां प्रस्तावित करेगा।

पशुपालन पर विशेषज्ञों की बैठक

पशुपालन पर कार्यदल की एक बैठक डॉ. हरदीप कुमार, आई.ए.एस., वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेरी विभाग की अध्यक्षता में 15 सितम्बर 2011 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य विषय राज्य में पशुधन संसाधनों की वर्तमान स्थिति व संरचना की समीक्षा करना तथा वर्ष 2020 और 2030 के लिए विभाग का परिदृश्य तैयार करना था। आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई विभिन्न परिचर्चा बैठकों के दौरान पशुपालकों द्वारा जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, उन पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला से यह तथ्य उभर कर सामने आया कि भैंस डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण अंग है और इससे राज्य में उत्पन्न होने वाले कुल दूध का 83 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त होता है। तथापि, गौ पशुओं की देसी नस्लों के संरक्षण व प्रवर्धन के साथ-साथ गैर-वर्णित गायों का संकर प्रजनन जारी रहना चाहिए। महानिदेशक ने सदन को किसानों के नजदीक प्रजनन व पशु स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधा उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त आनुवंशिक सुधार के द्वारा पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नई योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग पशुओं के कान में परंपरागत टैग लगाने के अतिरिक्त माइक्रो चिपों का उपयोग करके राज्य के सभी पशुओं की पहचान करने की योजना बना रहा है। इन पशुओं को पहचान संख्या प्रदान की जाएगी जिससे ओ. आई. ई. मेन्डेट के साथ सीरो-निगरानी व रोगों के नियंत्रण व निगरानी के लिए प्राथमिक आवश्यकता के रुप में प्रत्येक पशु की अमुक स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसका उपयोग इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए किया

कार्यदल के विशेषज्ञों के साथ चर्चा

जाएगा जिसे अभी तक ''द स्लीपिंग जाइंट'' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि यद्यपि, दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना वांछनीय है लेकिन इसका कार्यान्वयन संभवत: अभी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि संगठित क्षेत्र द्वारा दूध के बहुत अल्प भाग (25% से कम) की साज-संभाल की जा रही है। गाय के दूध की वसा के लिए जो वैधानिक मानक वर्तमान में 4 प्रतिशत है, उसकी पुन: समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि विदेशी तथा संकर नस्लों की गायों के दूध में वसा का अंश निश्चित रुप से न्यूनतम निर्धारित वैधानिक मानक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार गाय के दूध का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि जब इसकी तुलना भैंस के दूध में मौजूद उच्च वसा अंश से की जाए तो गाय का दूध कहीं बहुत पीछे न रह जाए। यह विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उच्च तकनीक वाली वाणिज्यिक डेरियों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी आशा है कि छोटी डेरी इकाइयों से युक्त कुटीर उद्योग के स्थान पर निकट भविष्य में व्यावसायिक डेयरियां स्थापित हो जाएंगी। रियायती दरों पर बिजली की उपलब्धता के साथ-साथ ऋण तथा अन्य प्रोत्साहनों की अनुपलब्धता इस क्षेत्र के वाणिज्यीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। ऋण तथा अन्य प्रोत्साहन/अनुदान कृषि के समकक्ष होने चाहिए। प्रत्येक राज्य में पशुधन का मानचित्रण करने के लिए नियोजन की नीचे से ऊपर की ओर वाली क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के संसाधनों, मांग, विपणनशीलता आदि को ध्यान में रखते हुए विशेष पशुधन क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। मुर्रा भैसों का दूध तथा इसके विशेष उत्पादों (उदाहरण के लिए मोज़रैला चीज) के लिए ब्राण्ड हरियाणा सृजित करने, पशुपालक किसानों की क्षमता निर्माण और कार्यबल का 70 प्रतिशत भाग बनने वाली महिलाओं के प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने का सुझाव दिया गया।

मत्स्य कृषकों के साथ परिचर्चा बैठक

हरियाणा किसान आयोग ने 23 सितम्बर 2011 को राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में मत्स्य कृषकों के साथ एक परिचर्चा बैठक आयोजित की। इस बैठक में हरियाणा के लगभग 25 मत्स्य पालकों ने भाग लिया। डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग; डॉ. डब्ल्यू.एस. लाकड़ा, अध्यक्ष; डॉ. के.के. वास, सदस्य, मात्स्यिकी पर कार्यदल के सदस्य; डॉ. एम.पी. यादव, परामर्शक, हरियाणा किसान आयोग; श्री पी.वी. सिंह, निदेशक, मात्स्यिकी, हरियाणा सरकार; मात्स्यिकी विभाग व इसी विभाग के अन्य अधिकारियों; केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के रोहतक केन्द्र के वैज्ञानिकों ने इस बैठक में भाग लिया। डॉ. डब्ल्यू.एस. लाकड़ा, निदेशक व कुलपति, केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान/अध्यक्ष, कार्यदल ने अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में मत्स्य कृषकों द्वारा सामना किए जाने वाले तीन मुख्य मुद्दों के बारे में बताया: 1) बीज की गुणवत्ता, 2) चारे की गुणवत्ता तथा 3) मत्स्य उत्पाद की बाजार तक पहुंच और लाभदायक मूल्य। उन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित मत्स्य विपणन मॉडल से भी अवगत कराया और यह परामर्श दिया कि इसे हरियाणा भी अपना सकता है। डॉ. आर.एस. परोदा ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में मछली पालन के साथ कृषि के विविधीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मत्स्य कृषकों को भी खेती करने वाले किसानों के समकक्ष माना जाना चाहिए तथा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं के साथ-साथ अनुदान, पानी व बिजली की दरों, ऋण आदि के मामले में भी मत्स्य पालकों को कृषि करने वाले किसानों के समकक्ष माना

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में विशेषज्ञों तथा मत्स्य कृषकों के बीच चर्चा

जाना चाहिए। उन्होंने सामुदायिक तालाबों को मत्स्य पालन के लिए कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में बताया, ताकि इससे मत्स्य पालक कृषकों को होने वाले जोखिम को कम किया जा सके। उन्होंने हरियाणा में सी-बास पालन की व्यवहारिकता, सम्मिलित प्रयासों से स्वयं सहायता समूहों व सहकारिताओं के माध्यम से मछलियों के भंडारण व परिवहन के लिए शीत श्रंखलाओं के विकास और 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' के समान 'राष्ट्रीय मात्स्यिकी मिशन' की आवश्यकता के अलावा हिसार में पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की सिफारिश की। बत्तखों, मुर्गियों, बकरियों, गोपशुओं, सूअरों के पालन के साथ-साथ; मत्स्य पालन के लिए अंतर-प्रजनन के कारण घटिया गुणवत्ता वाले मछली बीज की उपलब्धता, विषाक्तता से जुड़ी समस्या और खत्ते के कारण अमोनिया की मांग बढ़ जाने से सामुदायिक तालाबों का प्रदूषण कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका सामना मत्स्य कृषकों/मछली पालकों को करना पड़ रहा है और इन्हें सुलझाने की तत्काल आवश्यकता है। निदेशक, मात्स्यिकी ने मत्स्य कृषकों की सहायता के लिए पर्यावरणीय नीतियों में संशोधन की आवश्यकता के बारे में बताया। उनके अनुसार मत्स्य हैचरियों के लिए जल का प्रभार वाणिज्यिक दरों पर वसूल किया जाता है। जहां एक ओर कृषि को आय कर से मुक्त रखा गया है, वहीं मात्स्यिकी के मामले में ऐसा नहीं है। मत्स्य चारे, बीज आदि के लिए अनुदान का प्रावधान केवल पहले वर्ष ही है, जबकि इसे प्रति वर्ष दिया जाना चाहिए। मत्स्य पालकों ने भी तालाबों की निगरानी के लिए विनियमन प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने, मछली तालाबों में प्रदूषण की जानकारी संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला का प्रावधान करने, सरकार द्वारा उचित मूल्य पर सी-बास और तिलापिया का बीज उपलब्ध कराए जाने तथा मछली बाजारों में मत्स्य कृषकों के उत्पाद की बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं प्रदान करने जरुरत पर बल दिया गया है। अंत में आयोग के अध्यक्ष ने अपनी समापन टिप्पणी दी जिसके पश्चात डॉ. एम.पी.यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

एल.एल.आर.यू.वी.ए.एस. के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (एल.एल.आर.यू.वी.ए.एस.) के नए भवन परिसर का शिलान्यास 15 अगस्त 2011 के पवित्र दिन अपराह्न 4 बजे किया गया। यह शिलान्यास हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने हिसार-चंडीगढ़ मार्ग (एन एच 65) पर छठवे कि.मी. के पत्थर के पास किया। श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।

हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एल.एल.आर.यू.वी.ए.एस. के नए भवन का शिलान्यास करते हुए

शपथ ग्रहण समारोह

लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के पशुविज्ञान महाविद्यालय के बी.वी.एससी. तथा ए.एच. के 2006 बैच का शपथ ग्रहण समारोह पशुचिकित्सा सभागार में 11 जुलाई 2011 को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. हरदीप कुमार मुख्य अतिथि थे। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. परूथी ने उपाधि लेने वाले इस बैच के 52 छात्रों को व्यावसायिक नैतिक आचरण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. हरदीप कुमार ने नव स्नातकों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और सामान्य रुप से समाज व विशेष रुप से पशुओं के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने का आह्वाहन किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गायों व भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लों के सुधार व परिरक्षण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में बताया। स्नातकोत्तर विद्यापीठ के अधिष्ठाता डॉ. एस.सी. आर्य ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. कुलदीप सिंह ने समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया।

डॉ. ए.के. परूथी समारोह में शपथ दिलाते हुए

प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर उद्यमियों को समर्पित

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय में हाल ही में स्थापित व्यापार नियोजन एवं विकास इकाई ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की बी.पी.डी. इकाई और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (भा.कृ.अ.प.) की वित्तीय सहायता से कंसोर्टियम मोड पर प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर की स्थापना करके उसका शुभारंभ किया। इस इन्क्यूबेटर में उद्यमियों तथा शुरु होने वाली कंपनियों के लिए कार्यालय तथा प्रयोगशाला की सुविधाएं होंगी। डॉ. हरदीप कुमार, आई.ए.एस., कुलपति ने 15.07.2011 को एक सादे समारोह में यह इकाई उद्यमियों को समर्पित की और यह सूचित किया कि यह विश्वविद्यालय भारत के सभी पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों में इस वर्ष अप्रैल में बी.पी.डी. इकाई आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है और आज यह प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर आरंभ करने में भी प्रथम हो गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बहुत कम समय में यह उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बधाई दी। डॉ. ए.के. परूथी, अध्यक्ष, बी.पी.डी. ने सी.ओ.वी.एस. के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दूध में यूरिया पहचान की प्रौद्योगिकी के बारे में सूचित करते हुए बताया कि यह प्रौद्योगिकी देशभर में बहुत लोकप्रिय हो गई है तथा अनेक उद्यमी इसके लिए समझौता ज्ञापन करने/लाइसेंस प्राप्त करने के

डॉ. हरदीप कुमार, आई.ए.एस., कुलपति द्वारा उद्यमियों को प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर का समर्पण

लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दूध में यूरिया की पहचान के लिए किटों के वाणिज्यिक उत्पादन व विपणन हेतु नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन 5 वर्ष के लिए 8.5 लाख रुपये में एक उद्यमी के साथ किया गया है व दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि एक अन्य उद्यमी के साथ समझौता होने वाला है।

हरियाणा को ''कृषि कर्मण'' पुरस्कार

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने हरियाणा की राज्य सरकार को वर्ष 2010-11 के दौरान गेहूं का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए 'कृषि कर्मण' पुरस्कार प्रदान किया। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है और ऐसी सेवाएं प्रदान की हैं जिन्हें अपनाकर किसानों ने गेहूं का उल्लेखनीय उत्पादन लिया है। राज्य सरकार की उल्लेखनीय पहलों में शामिल हैं : उत्कृष्ट मृदा स्वास्थ्य व जल प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना; राज्य में बोए गए गेहूं के

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा

बीजों का पूर्ण उपचार सुनिश्चित करना; बीज प्रतिस्थापना की दर को बढ़ाना; पीले रतुआ रोग का समय पर व प्रभावकारी नियंत्रण; और टिकाऊ उत्पादन के लिए संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। डॉ. भूपिन्दर सिंह हुड्डा, माननीय मुख्यमंत्री ने यह पुरस्कार श्री परमवीर सिंह, माननीय कृषि मंत्री, श्री रोशन लाल, प्रमुख सचिव कृषि और श्री अशोक यादव, महानिदेशक, कृषि के साथ माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में प्राप्त किया।

हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष, डॉ आर एस परोदा ने हरियाणा के राज्य कृषि विभाग और कठोर परिश्रम करने वाले राज्य के किसानों को इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी।

श्री अशोक यादव का ब्रिस्बेन, आस्ट्रेलिया में पत्र प्रस्तुतीकरण

श्री अशोक यादव, आई.ए.एस., महानिदेशक, कृषि, हरियाणा ने 26-29 सितम्बर 2011 को ब्रिस्बेन, आस्ट्रे लिया में आस्ट्रेलियन सैंटर फार इंटरवेंशन एग्रीकल्चरल रिसर्च (ए.सी.आई.ए.आर.) द्वारा आयोजित पांचवीं संरक्षित कृषि विश्व कांग्रेस (डब्ल्यू.सी.सी.ए.) और तीसरी फार्मिंग उत्पादन डिजाइन (एफ.एस.आई.), कांफ्रेंस में भाग लिया। वहां उन्होंने 'हरियाणा, में संरक्षित कृषि : पूर्व अनुभव तथा भावी योजनाएं' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। वे एशिया-पेसेफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन (अपारी) तथा 'सिमिट' द्वारा भारत से चुने गए चार विशेषज्ञों में से एक हैं। डॉ. यादव ने हरियाणा में संरक्षित कृषि की सफलता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा राज्य की भावी योजनाओं से अवगत कराया जिनकी इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहना की गई। डॉ. विकास चौधरी जो सोसायटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नैचुरल रिसोरसेज एंड इम्पावरिंग रुरल यूथ, तरावड़ी, करनाल (हरियाणा) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने भी इस कांफ्रेंस में भाग लिया। श्री चौधरी ने प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में हरियाणा के किसानों की नवोन्मेषी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस राज्य के किसानों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत कीं। इस सम्मेलन में भा.कृ.अ.प. के अनेक विशेषज्ञों तथा संरक्षित कृषि पर कार्य कर रहे प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अनेक प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

श्री अशोक यादव आई.ए.एस., महानिदेशक, कृषि

आपके सुझावों का स्वागत है

कृपया निम्न पतों पर भेजें

हिसार कार्यालय :
हरियाणा किसान आयोग
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
हिसार - 125 004
फोन: +91-1662-289593
फैक्स: +91-1662-289511

शिविर कार्यालय:
हरियाणा किसान आयोग
किसान भवन, खांडसा मंडी,
गुड़गांव - 122 001
फोन.: +91-124-2300784

वेबसाइट : www.haryanakisanayog.org